भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4325
उत्तर दिनांक 02/04/2026 को दिया गया

देश में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का खनन

4325. श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार द्वारा देश में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और यूरेनियम के लिए किसी भी खान का अन्वेषण और उत्खनन शुरू किया गया है;

(ख) देश में दुर्लभ पृथ्वी धातुओं और कोबाल्ट का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) क्या सरकार अथवा निजी क्षेत्र ने, इन खनिजों से समृद्ध अन्य देशों के हितधारकों के साथ कोई दीर्घकालीन समझौते किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) हां। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक संघटक इकाई, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), देश के संभावित भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) और यूरेनियम की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एकीकृत और बहु-आयामी अन्वेषण कर रहा है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) सहित महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2021-22 और 2023-24 के बीच, जीएसआई ने देश में दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) को लक्षित करते हुए 166 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को संचालित किया। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 में, जीएसआई ने आरईई पर 78 अन्वेषण परियोजनाएं शुरू कीं और वर्ष 2025-26 के दौरान 92 परियोजनाएं शुरू कीं। खान मंत्रालय ने दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के 7 ब्लॉकों सहित 46 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने अन्वेषण लाइसेंस के 7 ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिसमें आरईई के दो ब्लॉक शामिल हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (आईआरईएल) को देश में उच्च शुद्धता वाले आरई ऑक्साइड के निष्कर्षण के लिए समुद्र तटीय सामग्री (बीएसएम) अयस्क से प्राप्त दुर्लभ मृदा (आरई) युक्त खनिजों को संसाधित करने का दायित्व सौंपा गया है। आईआरईएल तीन स्थानों पर काम कर रहा है, जिसमें खनिज रेत के एकीकृत खनन और प्रसंस्करण की सुविधा है और दुर्लभ मृदा के निष्कर्षण और परिशोधन के लिए पृथक सुविधाएं भी स्थापित हैं।

परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू), यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), यूरेनियम अयस्क के खनन और प्रसंस्करण में संलग्न है। वर्तमान में यूसीआईएल झारखंड राज्य में सात यूरेनियम खानों और दो अयस्क प्रसंस्करण संयंत्रों तथा आंध्र प्रदेश राज्य के तुम्मलापल्ले में एक यूरेनियम खान और संयंत्र का प्रचालन कर रहा है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार, एएमडी द्वारा आकलित दुर्लभ मृदा तत्वों के संसाधनों का अनुमान निम्नानुसार है -

(i) आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में टेरी, समुद्र तटीय रेत और अंतर्देशीय जलोढ़ में पाए जाने वाले 13.15 Mt मोनाज़ाइट [दुर्लभ मृदा तत्वों और थोरियम का एक खनिज] में लगभग 7.23 मिलियन टन (Mt) कुल दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (टीआरईओ) समतुल्य।

(ii) गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कठोर चट्टान क्षेत्रों में 1.29 Mt स्वस्थाने टीआरईओ समतुल्य ।

(ग) खान मंत्रालय के तत्वावधान में एक संयुक्त उद्यम (जेवी) खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) को लिथियम, कोबाल्ट, आरईई आदि जैसी विदेशी खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए स्थापित किया गया है। केएबीआईएल ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्राइन ब्लॉकों के अन्वेषण और खनन के लिए कैम्येन के साथ एक अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक, केएबीआईएल ने किसी भी देश या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ आरईई, कोबाल्ट और यूरेनियम के लिए कोई दीर्घ-कालिक समझौता नहीं किया है।

*****